



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127।  
No. 127।नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2012/वैशाख 24, 1934  
NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2012/VAISAKHA 24, 1934

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2012

फा. सं. 3-24/2012-बी एंड सीएस.—भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 जो,—

(ए) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं० एस. ओ. 44 (ई) तथा 45(ई) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) और (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 (2012 का 14)

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 कहा जाएगा।  
 (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012 (जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 3 के उप-विनियम (11) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
 "(11ए) कोई भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, प्रसारक से प्लेसमेंट शुल्क की मांग नहीं करेगा"
3. मूल विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
 "(8ए) उप-विनियम (7) एवं उप-विनियम (8) के तहत प्राधिकरण को प्रस्तुत प्रत्येक अंतःसंयोजन प्रस्ताव में, प्रसारकों द्वारा देय कैरिज शुल्क की गणना हेतु अपनाई गई पद्धति का उल्लेख होगा।"
4. मूल विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (14) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
 "(14ए) प्रत्येक प्रसारक, अपने चैनलों की विषय-वस्तु घोषित करेंगे तथा इस प्रकार के चैनलों की विषय-वस्तु में निम्न में से कोई भी एक जैसे समसामयिक मामले या सूचना-मनोरंजन या खेलकूद या बच्चे या संगीत या जीवन शैली या फिल्में या धार्मिक या भक्तिमय या सामान्य मनोरंजन (हिंदी) या सामान्य मनोरंजन (अंग्रेजी) या सामान्य मनोरंजन (क्षेत्रीय भाषा) के होंगे।

(14बी) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, प्रसारकों के चैनल को, ऐसे प्रसारक द्वारा घोषित विषय-वस्तु में शामिल करेंगे।"

(14सी) कोई भी प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से किसी विशेष चैनल नंबर के आबंटन की मांग नहीं करेगा।"

5. मूल विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (15) के परंतुक के बाद निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(15ए) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड में, उसके द्वारा पेशकश किए जाने वाले सभी चैनलों को उसी विषय-वस्तु में, जिसमें प्रसारक द्वारा एक विशेष चैनल निर्दिष्ट किया गया है, प्रदर्शित करेंगे एवं एक चैनल केवल, एक ही विषय-वस्तु में प्रदर्शित होगा।"

वसी अहमद, सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/142/12]

टिप्पणी : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट किया गया।

अनुबंध

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के पश्चात्, दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012 (2012 का 9) (जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है) अधिसूचित किया गया था। मूल विनियम विशेषतः डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली पर लागू होता है जबकि दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13), गैर एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली एवं एड्रेसेबल प्रणाली जैसे डीटीएच, आईपीटीवी आदि पर लागू होता है।

2. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्लेसमेंट शुल्क वसूलने के संबंध में एक प्रश्न उठा है। डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड(ईपीजी) के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसमें एमएसओ के

नेटवर्क पर दिखाए जाने वाले सभी चैनलों को एक आसान तरीके से समझाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है, ताकि उपभोक्ता आसानी से इस गाइड के द्वारा सभी चैनलों बारंबार बदलने की बजाए, अपनी पसंद के चैनल को चयनित कर सके। चैनलों का यह प्रदर्शन विषय-वस्तुवार हो सकता है, जहां एक विशेष विषय-वस्तु के सभी चैनलों को ईपीजी की विषय-वार सूची के तहत उस विषय में सूचीबद्ध दिया जा सकता है। अतः डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली में प्लेसमेंट शुल्क वसूलने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (11) में यह स्पष्ट है कि उपबंध किया गया है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा चैनल को एक विशिष्ट स्लॉट या बुके (समूह) में रखने पर जोर नहीं दिया जाएगा अन्यथा यह एक अनुचित शर्त होगी। इस उपबंध को बनाने की मंशा यह थी कि प्लेसमेंट शुल्क नहीं वसूला जा सकता है। तथापि, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए, संशोधित विनियम में विशिष्ट उपबंध किया गया है ताकि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, किसी भी प्रसारक पर कोई भी प्लेसमेंट शुल्क अधिरोपित न करें।

3. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा कैरिज शुल्क लगाने का वर्णन मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (12) एवं विनियम 4 के उप विनियम (7) एवं (8) तथा पैराग्राफ 15 से 17 में किया गया है। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्राधिकरण के पास प्रसारकों पर अधिरोपित की जाने वाली प्रति चैनल कैरिज शुल्क की मात्रा के साथ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की प्रतिलिपि दायर की जाएगी। डिजिटल प्रौद्योगिकी से चैनलों को ले जाने की क्षमता में कोई बाधा नहीं है। साथ ही उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस), उपभोक्ता संख्या की पूर्ण घोषणा होने से, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की अभिदान आय में प्रतिशत वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप, कैरिज शुल्क में काफी हद तक कमी होने की उम्मीद है। यह प्रकल्पित किया गया था कि प्राधिकरण के पास दायर किए जाने वाले अंतःसंयोजन प्रस्ताव में कैरिज शुल्क की धनराशि की गणना हेतु अपनाई गई पद्धति का विस्तार से उल्लेख होगा। इसे, अब अन्तर्स्थापित किए गए उप-विनियम में स्पष्ट कर दिया गया है।

4. दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के मूल विनियमों के विनियम 5 के उप विनियम (15) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को इस बात की छूट होगी कि वह प्रसारक द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए चैनलों के बुके से सब्सक्राइबर को प्रस्तावित चैनलों का पैकेजिंग तय करे। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा

चैनलों के प्लेसमेंट के संबंध में एक प्रश्न उठा है। उपलब्ध कराए जाने वाले चैनल को उसी विषय के अन्य चैनल की तुलना में, प्रतिकूल स्थिति में आने की घटना को रोकने के लिए, अब यह उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रसारक द्वारा चैनल की विषय-वस्तु निर्दिष्ट की जाएगी तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, चैनल को प्रसारक द्वारा घोषित चैनल की विषय-वस्तु में शामिल करेगा। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि एक विशेष विषय-वस्तु के सभी चैनल, उसके नेटवर्कों की इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड (ईपीजी) के तहत उसी विषय-वस्तु में निर्दिष्ट होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ता उन सभी चैनलों की सूची को देखने में समर्थ हो सकेगा जो कि विषय-वस्तुवार उपलब्ध है और इस तरह ग्राहक के लिए सेवाएं अधिक अनुकूल बनेगी।

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2012

**F. No. 3-24/2012-B & CS.**—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication), No.39,-----

- (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and
- (b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

1717 9012-2

**THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE SERVICES)  
INTERCONNECTION (DIGITAL ADDRESSABLE CABLE TELEVISION SYSTEMS)  
(FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2012**

**No. 14 of 2012**

**1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (First Amendment) Regulations, 2012.**

**(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.**

**2. In regulation 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as the principal regulations), after sub-regulation (11), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-**

**“(11A) No multi system operator shall demand from a broadcaster any placement fee.”**

**3. In regulation 4 of the principal regulations, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-**

**“(8A) Every Reference Interconnect Offer submitted to the Authority under sub-regulation (7) and sub-regulation (8) shall also contain the basis on which the carriage fee payable by the broadcaster has been determined.”**

**4. In regulation (5) of the principal regulations, after sub-regulation (14), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-**

**“(14A) Every broadcaster shall declare the genre of its channels and such genre shall be either News and Current Affairs or Infotainment or Sports or Kids or Music or Lifestyle or Movies or Religious or Devotional or General Entertainment (Hindi) or General Entertainment (English) or General Entertainment (regional language).**

**14(B) The multi system operator shall place the channels of a broadcaster in the genre declared by such broadcaster.**

14(C) No broadcaster shall demand from the multi-system operator to assign a particular number to its channels.”

5. In regulation (5) of the principal regulations, after proviso to sub-regulation (15), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(15A) Every multi system operator shall display, in his Electronic Programme Guide, all the channels offered by him, in the same genre in which a particular channel has been indicated by the broadcaster and one channel shall appear in only one genre.”

WASI AHMAD, Advisor (B & CS)

[ADVT. III/4/Exty./142/12]

**Note :** The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (First Amendment) Regulation, 2012.

### Explanatory Memorandum

### Annexure

1. After following an extensive consultation process, the Authority had notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012) (hereinafter referred to as the principal Regulation) on 30<sup>th</sup> April, 2012. While the principal regulation is specifically applicable for digital addressable cable TV systems, the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation 2004 (13 of 2004) is applicable for non-addressable cable TV systems and also addressable systems such as DTH, IPTV etc.
2. A question has arisen regarding charging of placement fee by the multi system operator. In the digital addressable cable TV systems, the technology provides for a Electronic Program Guide (EPG) wherein the channels being carried on an MSO's network can be arranged in a simple easy to understand manner so that the subscriber can easily go through this guide and select the channel of choice instead of flipping through all the channels. This display of channels can be genre-wise where all the channels of a particular genre can be listed under that genre in the genre-wise list of EPG. Thus, in digital addressable cable TV systems, there is hardly any justification for charging of the placement fee. In sub-regulation 11 of the regulation 3 of the principal regulation dated 30<sup>th</sup> April, 2012, it has clearly been provided that insistence by multi system operator on placement of a channel in a particular slot or bouquet amounts to imposition

of unreasonable terms. The intention of making this provision was that placement fee cannot be charged. However, to clarify the position in this regard, in the amendment regulation, a specific provision has been made so that the multi system operator does not charge any placement fee from any broadcaster.

3. The matter relating to charging of carriage fee by the multi system operator has been dealt with in sub-regulation 12 of regulation 3 and in sub-regulations 7 and 8 of the regulation 4 and also in the paragraphs 15 to 17 of the principal regulation. The multi system operators are to file a copy of the Reference Interconnect Offer with the Authority including the quantum of carriage fee per channel that would be charged from the broadcasters. With digital technology, the capacity to carry the channels is no longer a constraint. Also, the Subscriber Management System (SMS) provides the full declaration of the subscribers, increasing the percentage of subscription revenue to the multi system operator. With all these, the carriage fee is expected to go down substantially. It was presumed that the Reference Interconnect Offer that would be filed with the Authority would include the detailed basis on which the carriage fee has been worked out. The same has been clarified in the sub-regulation which has been inserted in this regard.

4. In sub-regulation 15 of regulation 5 of the principal regulation dated 30<sup>th</sup> April, 2012, a provision has been made that it shall be open to a multi system operator to decide the packaging of the channels offered to the subscribers from bouquet of channels provided to it by the broadcaster. A question has arisen regarding placement of channels by the multi system operator. To avoid any eventuality of a channel being placed in a disadvantageous position as compared to another channel of the same genre, a provision has now been made whereunder a broadcaster has to indicate the genre of a channel and the multi system operator has to include that channel in the genre declared by the broadcaster. The multi system operator is required to ensure that all the channels falling in a particular genre appear in its network's Electronic Programme Guide (EPG) under the same genre. With this the subscriber would be able to see the list of channels that are available genre-wise and thus making the service more customer friendly.